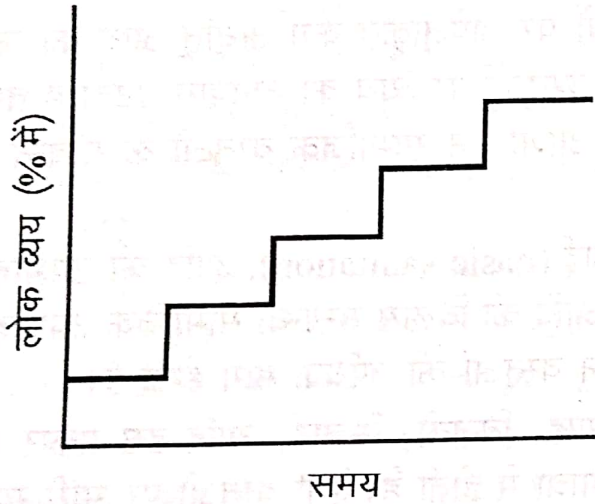


वहां मितव्ययिता की आशा नहीं की जा सकता है। एसा एसा  
 जन प्रतिनिधि ऐसे कर लगायेंगे जिनका भार उन पर नहीं पड़ेगा। प्रजातन्त्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जि  
 कर का भुगतान करने से वे लोग बच जाते हैं जिन्हें कर लगाने का अधिकार होता है। (".....T  
 government of the democracy is the only one under which the power which lays o  
 the taxes escapes the payment of them.")

सम्पत्ति के वितरण प्रभाव भी काफी महत्व का होता है। असमान वितरण की स्थिति में, निर्धन, उ  
 बहुमत में रहते हैं, ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं जिनसे वे अपनी स्थिति सुधारने के उपाय कर सकें। स्वाभाविक  
 ही है कि लोक व्यय में वृद्धि होगी।

(3) आपातकालीन स्थिति (युद्ध, आर्थिक मन्दी, आदि) तथा पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा [Emergenc  
 (Wars, Depreciation, etc.) and the Peacock-Wiseman Hypothesis]—पीकॉक तथा वाइजमैन  
 (Peacock and Wiseman) ने अपनी पुस्तक *The Growth of Public Expenditure in the Unite  
 Kingdom* में युद्ध, आर्थिक मन्दी जैसी संकटकालीन अवस्था (emergency) की भूमिका पर विचार किये



चित्र 4.1—लोक व्यय में असतत  
 वृद्धि (Discrete increase)

growth) नहीं होती है बल्कि अनियमित रूप से छलांग (jump) लगाते हुए, जैसे मकान की सीढ़ी। इसे  
 चित्र 4.1 में दिखाया गया है।

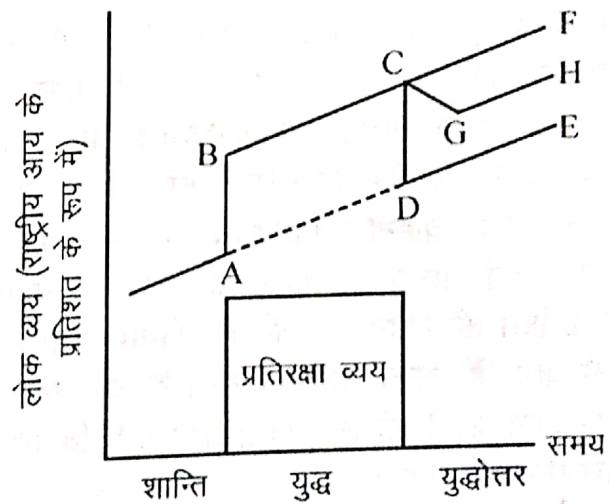
विकासशील देशों में पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा के सदृश (analogous) ही 'प्लीज प्रभाव' (Please  
 Effect) है। इन देशों में लोक व्यय, विशेषकर उपभोग-सम्बन्धी लोक व्यय, में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि  
 ऐसे व्यय के लिए साधन उपलब्ध हैं। कर राजस्व में वृद्धि होने पर सार्वजनिक बचत में वृद्धि होने के स्थान  
 पर सरकारी उपभोग व्यय में ही अधिक वृद्धि होती है।



पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा का अनुमोदन मस्रोव दम्पति ने भी किया है। उनके शब्दों में, “युद्ध जैसे राष्ट्रीय संकटों के समय में लोक व्यय में अस्थायी, किन्तु बाह्य वृद्धि की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है और इसके लिए मतदाता पुराने कर-देहली को पार करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तथा कर के स्तर में ऐसी वृद्धि को स्वीकार कर लिया जाता है जिसका पहले विरोध किया जाता था।” लोक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या के सिलसिले में आपातकाल की भूमिका के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं और आपातकालीन संकट का युद्ध सबसे अच्छा उदाहरण है। इसीलिए जे. एम. बुखानन (Buchanan) का कहना है कि लोक व्यय में वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकेला तत्व यदि कोई है तो वह युद्ध और युद्ध की आशंका है। आधुनिक युद्ध तथा प्रतिरक्षा की लागत अत्यन्त बढ़ गयी है। सरकारी बजट, विशेषकर केन्द्रीय सरकार का, का एक बड़ा भाग सेना के विभिन्न अंगों पर खर्च किया जाता है। कुछ उदाहरण लें—द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इंग्लैण्ड प्रतिदिन 15 मिलियन पाउण्ड खर्च करता था। स्टॉकहोल्म के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अनुसन्धान संस्थान के अनुसार 1978 में विश्व का सेना पर कुल व्यय 400 बिलियन डॉलर था जो उस वर्ष अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका की समग्र राष्ट्रीय आय से भी अधिक रकम थी। 1987 में यह बढ़कर 930 बिलियन डॉलर हो गया। पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री श्रीमती वेनजीर भुट्टो ने बताया कि 1985-86 में पाकिस्तान का शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय दो डॉलर था जबकि सेना पर 2,000 डॉलर। स्पष्ट ही है कि इस बड़े पैमाने पर प्रतिरक्षा व्यय से लोक व्यय का स्तर बढ़ेगा ही।

मस्रोव ने अपनी पुस्तक *Fiscal System* में इस बात की विस्तार से जांच करने की कोशिश की है कि युद्धकाल में लोक व्यय के हठात काफी बढ़ जाने के पश्चात् युद्धोत्तर काल में इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी। इसके लिए चित्र 4.2 को देखा जाय। चित्र में यह

दिखाया गया है कि युद्ध के कारण प्रतिरक्षा व्यय में हठात वृद्धि हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि शान्तिकालीन लोक व्यय की प्रवृत्ति A बिन्दु पर बदल जाती है और B बिन्दु से यह नई दिशा में बढ़ती है जो लोक व्यय के स्तर में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। युद्धोत्तर काल में लोक व्यय की दिशा क्या होगी, इस सम्बन्ध में तीन सम्भावनाओं को दिखाया गया है : (1) युद्धोत्तर काल में लोक व्यय D बिन्दु पर आकर पुरानी राह DE को ग्रहण कर सकती है। ऐसी स्थिति विस्थापन प्रभाव की उपस्थिति में होगी। (2) विस्थापन प्रभाव की उपस्थिति में लोक व्यय युद्धकालीन राह पर ही युद्धोत्तर काल



चित्र 4.2

में भी CF के अनुसार बढ़ सकता है। (3) विस्थापन प्रभाव की स्थिति में यह भी सम्भव है कि युद्धोत्तर काल में लोक व्यय की प्रवृत्ति CGH के अनुसार बढ़ने की हो। पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा इसी सम्भावना को अधिक सही मानती है। युद्धकाल में लगाये गये नये करों में से कुछ युद्ध की समाप्ति के बाद भी रह जा सकते हैं। फलतः युद्धोत्तर काल में लोक व्यय में स्थायी वृद्धि हो जायगी, लेकिन युद्धकाल की तुलना में कम।

पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा के अनुसार किसी बड़ी गड़बड़ी के नहीं होने पर लोक व्यय में वृद्धि स्थिर गति से होगी। 1960 के दशक के अन्तिम चरण में पश्चिमी देशों में लोक व्यय में विस्फोटक वृद्धि हुई। इस वृद्धि की व्याख्या किसी संकट या आपात स्थिति के रूप में नहीं हो सकती। यह कहना अधिक उचित होगा कि पीकॉक-वाइजमैन अवधारणा केवल संकेत करती है, ठोस व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती।

### अनिवर्ती चक्र प्रभाव (Ratchet Effect)

यह अवधारणा कि किसी उथल-पुथल के कारण लोक व्यय में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा इसके पश्चात् लोक व्यय में वृद्धि की व्याख्या अनिवर्ती चक्र प्रभाव के रूप में भी की जा

सकती है। उथल-पुथल के समाप्त हो जाने के बाद लोक व्यय अपने पुराने स्तर पर लौट नहीं जाता है निम्न कारणों से :

(i) करदाता लोक व्यय के उच्च स्तर से आदी हो जाता है तथा उस स्तर को ही सामान्य स्तर मानने लगता है।

(ii) उथल-पुथल की अवधि में लिये गये ऋण को वाद में भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए वित्त को प्रवन्ध करना होता है।

(iii) उथल-पुथल की अवधि में सरकार करदाताओं से जो वादा करती है, उसे इस स्थिति के समाप्त होने पर निभाना पड़ता है।

इन तीनों को सम्मिलित रूप से अनिवर्ती प्रभाव कहा जा सकता है। इस प्रभाव के कारण लोक व्यय ऊंचे स्तर पर ठहर जाता है।

(iv) अन्त में, निरीक्षण प्रभाव (Inspection effect) उथल-पुथल की समाप्ति के पश्चात् क्रियाशील हो सकता है। इस प्रभाव के अन्तर्गत करदाता एवं सरकार अपनी स्थिति एवं प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करते हैं। इस सिलसिले में वैसी आवश्यकताओं की खोज हो सकती है जिन पर पूर्व में ध्यान नहीं गया था। यह लोक व्यय के स्तर में वृद्धि को उचित ठहरा सकता है।

अनिवर्ती चक्र एवं निरीक्षण प्रभाव संयुक्त रूप से कार्य करते हुए ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि लोक व्यय उच्च स्तर पर बने रहें तथा अगले उथल-पुथल के बाद फिर और ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं।<sup>1</sup>